(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारी कागज के घटते दामों और उसके परिणामस्वरूप आयातित अखबारी कागज के अधिकाधिक न्यूनतर दामों पर उपलब्ध होने से स्वदेशी अखबारी कागज विनिर्माता उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, कई अखबारी कागज विनिर्माता मिलों, नामतः मै० "नेपा" लि०, मै० औरंगाबाद पेपर मिल्स लि० और मै० रामा न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि० ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है और कुछ एककों, नामतः मै० हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि० ने या तो अपना उत्पादन कम कर दिया है अथवा कागज की अन्य किस्मों के उत्पादन को अपना लिया है।

(घ) और (ङ) वाणिज्य मंत्रालय में नामित प्राधिकरण ने भारतीय अखबारी कागज विनिर्माता संघ द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर 20.12.96 को संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और रूस से अखबारी कागज के आयात के विरुद्ध एंडी डम्पिंग जांच शुरू कर दी है। सीमा-शुल्क अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत यह प्राधिकरण कोई सिफारिश करने से पहले सभी संबद्ध पार्टियों द्वारा किये गये अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया अपनाता है। अखबारी कागज के मामले में जांच प्रगति पर है और कोई भी अंनतिम अथवा अंतिम निष्कर्ष अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं।

खाद्यान्न की खरीदी गयी मात्रा

*209. **श्री रामजीलाल:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और चालू वर्ष में अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की कितनी-कितनी मात्रा में खरीद की गयी;

(ख) क्या उपरोक्त मात्रा पिछले वर्षों के दौरान खरीदी गयी मात्रा की तुलना में कम थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) विपणन मौसम 1993-94 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए खरीदे गए चावल और गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ग) विपणन मौसम 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए चावल की वसूली में संतोषजनक प्रगति हो रही है और 4.3.1997 को स्थिति के अनुसार यह वसूली 93.87 लाख टन पर पहुंच गई है जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख को 77.05 लाख टन की वसूली हुई थी। 1996-97 में यह वसूली बढ़कर 115 लाख टन होने की संभावना है जबकि पिछले वर्ष केवल 99.49 लाख टन की वसूली हुई थी।

रबी विपणन मौसम 1996-97 में 81.82 लाख टन गेहूं की वसूली हुई है जबकि पिछले वर्ष में 123.27 लाख टन गेहूं की वसूली हुई थी। यह गिरावट मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31 लाख टन कम उत्पादन होने और प्राइवेट व्यापारियों द्वारा अधिक खरीददारी करने के कारण हुई है।

विवरण

(लाख टन में)

	खरीदी गई गेहूं की मात्रा	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (4.3.97)
क.	केन्द्रीय पूल के लिए खरीदी	128.35	118.69	123.27	81.52
ख.	आयात	4.76	शून्य	शून्य	5.40
	जोड़ (क+ख)	113.11	118.69	123.27	87.92
	खरीदे गये चावल की मात्रा				
क.	केन्द्रीय पूल के लिए खरीदी	136.51	134.03	99.49	93.07
ख.	केन्द्रीय पूल के लिए अंशदान न देने वाले राज्यों द्वारा खरीदी गई	6.09	3.02	0.97	5.64
ग.	आयात	0.56	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (क+ख+ग)	143.16	137.05	100.46	99.71

Machines purchased by CIL lying unused

*210. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Expensive machines lying unused at CIL" as reported in the Statesman dated the 15th January, 1997;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether RAMBN machines purchased by CIL for installation at various coalfields are lying unused; and

(d) the cost of the machines and the reasons why CIL purchased such machines when its subsidiaries are running in losses?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The news item referred to the following:

(1) Coal India Ltd. (CIL) have installed 80 Remote Area Business Message Network (RABMN) terminals from the department of Telecom at an investment of Rs.3.20 lakhs each;

(2) some of these are lying idle;

(3) These machines were installed to replace fax facility as a quick mode of transmission of messages;

(4) RABMN is a more effective and a cheaper mode of communication than fax;

(5) Though some of the coal companies are running at a loss, wasteful investment in installing the 80 RABMN terminals have been made;

(6) All RABMN machines are lying idle for want of operators; and

(7) CIL is paying Rs. 56 lakhs annually to M/s. India Satcom Ltd. even when these terminals are not being used.